



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 23 अगस्त, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न० बिल/1-45/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 19) जो आज दिनांक 23-8-2006 को

हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम संक्षिप्त नाम योजना (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। और प्रारम्भ।

(2) यह 4 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1977 का 12

2. हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें धारा 67 का इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित रखा प्रतिस्थापन।
जाएगा, अर्थात्:-

"67. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण.—(1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण होगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) ऐसे अन्य सदस्य, जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं,

जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, यदि समीचीन समझे, किसी भी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोनों, नियुक्त कर सकेगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन होगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

- (4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य किसी भी प्रकार के वेतन के हकदार नहीं होंगे परन्तु ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे विहित किए जाएं।
- (5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसे उक्त प्राधिकरण द्वारा बनाए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।”।

धारा 68 का

प्रतिस्थापन। अर्थात्:-

3. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,

“68. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का निगमन.-

- (1) प्रत्येक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जब तक उत्सादित न हो, एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा धारा 66 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (2) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से उत्सादित कर सकेगी, जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए और उक्त प्राधिकरण तदनुसार उत्सादित हो जाएगा।
- (3) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्सादित करने की तारीख से ही ऐसी सभी सम्पत्तियां, परिसम्पत्तियां, दायित्व, निधियां, शोध रकमें, जो उक्त प्राधिकरण द्वारा वसूली योग्य हैं और कर्मचारी जो उसमें निहित हैं, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकरण या निगम या अधिकरण, जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, द्वारा वसूली योग्य होंगे और उसमें निहित हो जाएंगे।”।

2006 के
अध्यादेश
संख्यांक 3
का निरसन
और

4. (1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृत्तियां।

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने तीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों नामतः ढली, न्यू शिमला (कसुम्पट्टी) तथा टूटू का नगर निगम शिमला में विलय करने और साथ ही नालागढ़ तथा बददी-बरोटीवाला क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित करने का विनिश्चय किया है। वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में किसी भी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्सादित करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है ताकि उपरोक्त निर्दिष्ट तीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का हिमाचल प्रदेश नगर निगम, शिमला में विलय किया जा सके। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त अधिनियम में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष को नियुक्त करने का कोई उपबन्ध नहीं है, इसलिए यह भी विनिश्चय किया गया कि अधिनियम में इस प्रभाव का उपबन्ध किया जाए कि, राज्य सरकार, यदि समीचीन समझे, किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोनों नियुक्त कर सके। इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अधिनियम में समुचित रूप से संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

2. क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश संख्यांक 3) अधिसूचना संख्या टी0सी0पी0-ए0 (3)-6/2006 द्वारा तारीख 04 जुलाई, 2006 को प्रख्यापित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 4 जुलाई, 2006 को प्रकाशित किया गया था। अब उपर्युक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

3. यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:
तारीख.....2006.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को किसी भी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दोनों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त करता है। उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, यदि किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसे प्राधिकरण की निधियों में से संदाय किया जाएगा। इस प्रकार इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को किसी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए, यदि समीचीन समझा जाए, उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के भत्तों के संदाय हेतु उपबन्ध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त विधेयक का खण्ड 3 राज्य सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 67 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्सादित करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 19 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING
(AMENDMENT) BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Town and Country
Planning Act, 1977 (Act No.12 of 1977).*

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh
in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Act, 2006.

Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on
the 4th day of July, 2006.

2. For section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (hereinafter referred to as the “principal Act”), the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of section
67.

“67. **Special Area Development Authority.**—(1) Every special area shall have Special Area Development Authority, which shall consist of—

(a) the Chairman; and

(b) such other members as the State Government may determine from time to time,

who shall be appointed by the State Government.

(2) The State Government may, if consider expedient, appoint Vice-Chairman or Chief Executive Officer or both, for any Special Area Development Authority.

- (3) The Chief Executive Officer shall be a whole time officer of the Special Area Development Authority who shall receive such salary and allowances and shall be subject to such terms and conditions as may be determined by the State Government.
- (4) The Chairman, Vice-Chairman and members shall not be entitled to any salary but shall receive such allowances as may be prescribed.
- (5) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified by regulations made by the said Authority.”.

Substitution
of section
68.

3. For section 68 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“68 Incorporation of Special Area Development Authority.—

- (1) Every Special Area Development Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal, unless abolished, with power to acquire, hold and dispose of property, both moveable and immovable, and to contract, and shall sue and be sued by the name specified in the notification under sub-section (1) of section 66.
- (2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, abolish the Special Area Development Authority constituted under section 67 of the Act from such date as may be specified therein and the said Authority shall stand abolished accordingly.
- (3) On and with effect from the date of abolition of the Special Area Development Authority all properties, assets, liabilities, funds, dues and staff which are realisable and vested in the said Authority shall be realisable and shall vest in such authority or corporation or agency, as the case may be, as the State Government may decide.”.

Repeal of
Ordinance
No. 3 of
2006 and
savings.

4. (1) The Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has decided to merge three Special Area Development Authorities namely Dhalli, New Shimla (Kasumpti) and Totu with Municipal Corporation, Shimla and also to constitute Special Area Development Authority for Nalagarh and Baddi—Barotiwala Areas. At present there is no provision in the Town and Country Planning Act, 1977 to abolish any Special Area Development Authority, hence it is considered necessary to make suitable provision in the Act *ibid* so that the above referred three Special Area Development Authorities could be merged in the Municipal Corporation, Shimla. Further, there is no provision in the Act *ibid* to appoint Chief Executive Officer and Vice-Chairman of the Special Area Development Authority, therefore, it has also been decided to make a provision in the Act to the effect that the State Government may, if consider expedient to appoint, Vice- Chairman or Chief Executive Officer or both for any Special Area Development Authority. As such, in order to achieve the above objects, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably.

2. Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2006 (Ordinance No. 3 of 2006) *vide* notification No. TCP-A(3)-6/2006 dated 4-7-2006 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 4-7-2006. Now the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

3. The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

Rangila Ram Rao,
Minister-in-Charge.

Shimla:

Dated.....2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to appoint Vice- Chairman or Chief Executive Officer or both for any Special Area Development Authority. The Vice- Chairman or Chief Executive Officer, if appointed to any Special Area Development Authority, shall be paid out of the funds of such Authority. As such, there shall be no additional expenditure out of State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to appoint Vice- Chairman or Chief Executive Officer for any Special Area Development Authority, if consider expedient and to make rule providing for payment of allowances to the Chairman, Vice-Chairman and members. Further clause 3 of the Bill empowers the State Government to abolish the Special Area Development Authority, constituted under section 67, by notification in the Official Gazette. These delegation of powers are essential and normal in Character.